नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 146
दि. 25.09.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रधानमंत्री 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं में 91,770 करोड़ रुपये से अधिक की स्वच्छ ऊर्जा और पारेषण परियोजनाएं शामिल होंगी

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 16,050 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री राजस्थान से तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे राज्य और उत्तरी क्षेत्र के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह लगभग 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो-2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे और 1,22,100 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 1:45 बजे बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पीएम कुसुम लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री

मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो-2025 (यूपीआईटीएस-2025) का उद्घाटन करेंगे।

यह व्यापार मेला, "परम स्रोत यहीं से शुरू होता है" विषय पर 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके तीन मुख्य उद्देश्य होंगे: नवाचार, एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। एक त्रि-आयामी क्रेता रणनीति अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं, घरेलू व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) क्रेताओं और घरेलू व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) क्रेताओं को लक्षित करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे।

यूपीआईटीएस-2025 राज्य की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, सशक्त एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को एक ही मंच पर प्रदर्शित करेगा। इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष आदि प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा।

नवरात्र पर 3.95 लाख विद्यार्थियों को यूपी सरकार की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देंगे तोहफा

लखनऊ (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसमें करीब 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यह पहली बार होगा, जब छात्रों को सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले उन्हें दिसंबर महीने में छात्रवृत्ति मिलती थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसमें करीब 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार 26 सितंबर से छात्रवृत्ति वितरण की शुरूआत करने जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में लगभग चार लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इसके तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में खुद डेढ़ हजार लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

पहली बार होगा ऐसा

बता दें कि यह पहली बार होगा, जब छात्रों को सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले उन्हें दिसंबर महीने में छात्रवृत्ति मिलती थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं।

यही वजह है कि इसको लेकर फैसला बदला गया है। इसके तहत चालू सत्र में छात्रवृत्ति योजना में पूर्वदशम (कक्षा नौ-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के लिए सात सितंबर तक आए आवेदनों को शामिल किया गया है।

3.95 लाख में किस वर्ग के कितने विद्यार्थी?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब 26 सितंबर को पहले चरण का छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने प्रख्यात कन्नड़ लेखक और विचारक श्री एस.एल. भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रख्यात कन्नड़ लेखक और विचारक श्री एस.एल. भैरप्पा के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें एक ऐसा महान व्यक्तित्व बताया, जिन्होंने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया और भारत की आत्मा में गहराई तक उतर गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय साहित्य, विशेषकर कन्नड़ साहित्य में श्री भैरप्पा के योगदान ने राष्ट्र के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में जेप्टो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

समझौता ज्ञापन से युवा नौकरी चाहने वालों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से नए अवसर खुलेंगे

समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान जेप्टो 10,000 नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा, जिससे शहरी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

एनसीएस पोर्टल पर अब तक लगभग 7.5 करोड़ रिक्तियां उपलब ध कराई गई हैं

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रोजगार के अवसरों के साथ-साथ युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और जेप्टो के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

डॉ. मांडविया ने अपने संबोधन में कहा, "राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच एक अनूठे सेतु के रूप में उभरा है। अपनी स्थापना के बाद से 52 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ताओं और लगभग 7.5 करोड़ रिक्तियों के साथ एनसीएस ने स्वयं को सभी रोजगार-संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में स्थापित किया है।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य विश्व स्तरीय डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एनसीएस पोर्टल को मजबूत करने से नौकरी चाहने वालों को उनकी स्थान आवश्यकताओं और संबंधित योग्यताओं के अनुरूप अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी।"

मंत्रालय और जेप्टो के बीच सहयोग का स्वागत करते हुए डॉ. मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगी, साथ ही जेप्टो को मानव संसाधन के उपयुक्त प्रतिभा पूल से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री वंदना गुरनानी ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय और जेप्टो के बीच समझौता ज्ञापन औपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने को और बढ़ावा देगा।

लद्दाख पर प्रेस विज्ञप्ति

1. श्री सोनम वांगचुक द्वारा 10-09-2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर Apex Body Leh AüSX Kargil Democratic Alliance के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समितियों के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुईं। 2. इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया ने लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने और भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही, 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

भूमध्य सागर में तैनाती के तहत आईएनएस त्रिकंद साइप्रस के लिमासोल पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट पोत-आईएनएस त्रिकंद, भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के दौरान 21 सितंबर 2025 को साइप्रस के दक्षिणी तट पर स्थित लिमासोल पहुंचा।

वहां पहुंचने पर पोत के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुलकर्णी ने साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त श्री मनीष और साइप्रस नौसेना के कमांडर, कमोडोर मिनास सोलोमोनिडेस से मुलाकात की।

बंदरगाह पर प्रवास के दौरान पेशेवर संवाद, योग और जहाज पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान गतिविधियां आयोजित हुईं। 23 सितंबर 2025 को जहाज पर आगंतुकों का भी स्वागत किया गया।

आईएनएस त्रिकंद के इस तटीय शहर पहुंचने से साइप्रस के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग सुदृढ़ होगा और समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण पहल में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। भारतीय नौसैनिक पोत के भ्रमण से दोनों देशों के लोगों के आपसी संपर्क और सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही भारत और साइप्रस की दीर्घकालिक मैत्री और साझा मूल्यों को भी बल मिलेगा।

भारतीय पोत की साइप्रस की बंदरगाह यात्रा दोनों देशों के साझा रणनीतिक हितों और भूमध्यसागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के पारस्परिक संकल्प को दशार्ती है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 'सजलम भारत शिखर सम्मेलन' के अंतर्गत 'कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और एनआरएससी हैदराबाद के राज्यों ने "कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी" पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। साथ ही लेह से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दूरदराज के गांवों तक के पांच जमीनी स्तर के ग्राम पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी

(जीएनएस)।

केंद्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, ने 'कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी' विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन 'सुजलम भारत' शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य देशभर से जमीनी अनुभव और सुझाव लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस दृष्टि के अनुरूप है जिसमें जमीनी स्तर के विचारों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में शामिल करने पर बल दिया गया है।

सुजलम भारत शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग, (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), ने "कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी" विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। आज आयोजित कार्यशाला में चुनिंदा राज्यों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे कि लेह से लेकर तमिलनाडु तक और अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दूरदराज के गांवों से ग्राम पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों, साथ ही एनआरएससी, हैदराबाद जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।

कार्यशाला की अध्यक्षता सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने की, जिसमें प्रमुख वक्ताओं में श्री योगेश पैठणकर, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी, और सुश्री अर्चना वर्मा, एएस और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) शामिल थे और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य नोडल अधिकारी, क्षेत्र के विशेषज्ञ और जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती अर्चना वर्मा, एएसएमडी-एनडब्ल्यूएम ने बैठक का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों को आकार देने हेतु जमीनी स्तर पर सुझाव प्राप्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छह क्षेत्रीय विषयगत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुशल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों का योगदान आवश्यक है।

श्री योगेश पैठणकर, सदस्य (जल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति), केन्द्रीय जल आयोग ने अपने संदर्भ प्रस्तुतिकरण में मीठे जल संसाधनों पर दबाव कम करने हेतु जल मांग प्रबंधन हेतु कार्यान्वयन रणनीतियों पर प्रकाश डाला।कार्यशाला में कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रचार और स्केलिंग पर ध्यान केंद्रित करके इस प्रमुख रणनीति पर चर्चा की गई। इस विषय के प्रमुख पहलुओं में शामिल थे:

कृषि दक्षता: नहर और भूजल-सिंचित क्षेत्रों में सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना, और खेत में जल दक्षता में सुधार करना। सीडब्ल्यूसी जलवायु लचीलापन के लिए सटीक कृषि को भी बढ़ावा दे रहा है और सूखा-प्रतिरोधी और कम जल-गहन फसलों की ओर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है।

आधुनिकीकरण और स्वचालन: सीडब्ल्यूसी तृतीयक नहर वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रहा है और जल प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसमें जल संसाधन योजना, संवहन दक्षता बढ़ाने, वितरण को अनुकूलित करने, लीक का पता लगाने और कृषि, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी करने में अनुप्रयोग शामिल हैं।

जल संरक्षण और लेखांकन: इस विषय में घरों और उद्योगों के लिए जल-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, थोक जल आपूर्ति की निगरानी करना और गैर-लाभकारी जल नुकसान को कम करना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

- राज्य में नई 17 तहसीलों के गठन को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी, कुल तहसीलों की संख्या अब 265 होगी
- नए वाव-थराद जिले के गठन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का एक और जनोन्मुखी निर्णय
- 2013 के बाद पहली बार जिला-तहसीलों की संख्या में बड़ा फेरबदल होगा
- प्रधानमंत्री ग्रामोत्थान योजना का लाभ मिलने से नवगठित होने वाले तहसील मुख्यालयों का शहरी तर्ज पर विकास हो सकेगा
- प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकसित भारत@2047 के संकल्प में विकसित गुजरात@2047 के लिए नई तहसीलों का गठन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा

गांधीनगर, 24 सितंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने राज्य के अविरत विकास को गति देने वाला महत्वपूर्ण जन हितकार निर्णय किया है।

क्रम	जिला	मूल तहसील/तहसीलों के नाम	नई प्रस्तावित तहसील का नाम	प्रस्तावित मुख्यालय
(1)	महिसागर/पंचमहाल	संतरामपुर तथा शहेरा	गोधर	गोधर
(2)		लुणावाडा	कोठंबा	कोठंबा
(3)	नर्मदा	डेडियापाडा	चीकदा	चीकदा
(4)	वलसाड	वापी ग्राम्य, कपराडा, पारडी	नाना पोंढा	नाना पोंढा
(5)	बनासकाँठा	थराद	राह	राह
(6)		वाव	धरणीधर	डीमा
(7)		काँकरेज	ओगड	थरा
(8)		दाँता	हडाद	हडाद
(9)	दाहोद	झालोद	गोविंद गुरु लीमडी	लीमडी
(10)		फतेपुरा	सुखसर	सुखसर
(11)	छोटा उदेपुर	चेतपुर पावी	कटवाल	कटवाल
(12)	खेडा	कपडवंज तथा कठलाल	फागवेल	कापडीवाव (चिखलोड)
(13)	अरवल्ली	भिलोडा	शामळाजी	शामळाजी
(14)		बायड	साठंबा	साठंबा
(15)	तापी	सोनगढ	उकाई	उकाई
(16)	सूरत	मांडवी	अेठ	अेठ
(17)		महुवा	अंबिका	वलवाडा

राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों, जनता के सभी वर्गों तथा पदाधिकारियों की भावनाओं तथा प्रस्तुतियों पर सकारात्मक प्रतिभाव देते हुए बनासकाँठा जिले का विभाजन कर नए वाव-थराद जिले तथा राज्य की वर्तमान 21 तहसीलों का विभाजन कर नई 21 तहसीलों के गठन के प्रस्ताव को सर्वसंमति से मंजूरी दी है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशासनिक सरलीकरण का जो विचार दिया है, उसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में वर्तमान राज्य सरकार वेगवान बना रही है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में शासन में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण से जिला-तहसील स्तरीय कार्यालयों के साथ कामकाज में सुगमता आए तथा नया तहसील मुख्यालय नजदीक में प्राप्त होने से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सहित सर्वग्राही सुविधाओं में वृद्धि हो और सुदूरवर्ती गाँवों से तहसील मुख्यालय पर आने-जाने में समय, शक्ति तथा धन की बचत हो; ऐसे जन हितकारी उदार दृष्टिकोण से इन नई 17 तहसीलों के गठन को मंजूरी दी है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि वाव-थराद जिले में वर्तमान बनासकाँठा जिले की 6 तहसीलों वाव, थराद, सुईगाम, भाभर, दियोदर तथा लाखणी का समावेश कर थराद को जिला मुख्यालय बनाते हुए वाव-थराद जिले के गठन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

ब्लॉक के कारण 25 सितम्बर की पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी

राजकोट, 24 सितम्बर, 2025

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर क्षेत्र में रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाने, गोरखपुर-डोमिनगढ़ के बीच 4 किमी नई तृतीय लाइन और गोरखपुर-नखहा जंगल के बीच 5 किमी का दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के चलते राजकोट मंडल से होकर जानेवाली 25 सितम्बर, 2025 की ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

25 सितम्बर, 2025 को पोरबंदर से चलने वाली ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी -गोंडा-गोरखपुर-पनियहवा-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी-औंड़िहार-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी।

इस मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सांगली, बापूधाम मोतिहारी और चकिया स्टेशनों पर नहीं रूकेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

साबरमती लोको शेड द्वारा WAG-9HC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पहला इंटरमीडिएट ओवरहॉल (IOH) सफलतापूर्वक संपन्न

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के साबरमती लोको शेड ने अपनी उल्लेखनीय प्रगति को दशार्ते हुए उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हअक्र-9ल्ठउ का पहला इंटरमीडिएट ओवरहॉल (क्ष्डल) सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उपलब्धि लोको नं. 32322 पर हासिल की गई, जिसने शेड की तकनीकी दक्षता और समर्पण को और सशक्त रूप से स्थापित किया है।

साबरमती शेड की स्थापना वर्ष 1978 में टक्र डीजल उ्ट4 लोकोमोटिव के रखरखाव हेतु की गई थी। वर्ष 2009 से शेड ने उच्च हॉर्स-पावर हउक्र्ष्ठ डीजल लोकोमोटिव का रखरखाव प्रारंभ किया और निरंतर अपनी क्षमताओं का विस्तार करता रहा। मार्च 2023 में शेड को थ्री-फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान कर्मचारियों ने वड़ोदरा, वटवा तथा वलसाड इलेक्ट्रिक शेड से प्रशिक्षण प्राप्त कर अल्प समय में आवश्यक कौशल अर्जित किया। तत्पश्चात, अप्रैल 2025 से शेड ने सबसे शक्तिशाली हअक्र्-2इ लोकोमोटिव का रखरखाव शुरू किया।

केवल डेढ़ वर्ष के भीतर ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखरखाव का अनुभव प्राप्त करते हुए शेड ने क्ष्डल कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न किया। उल्लेखनीय है कि क्ष्डल शेड्यूल हर छह वर्षों में किया जाता है, जिसमें लोकोमोटिव की सभी प्रणालियों का व्यापक निरीक्षण और ओवरहॉल शामिल होता है, ताकि अगले छह वर्षों तक निर्बाध एवं विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी को अपने कौशल में निरंतर वृद्धि कर भारतीय रेल की सेवाओं को विश्वस्तरीय स्तर तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया।

यह उपलब्धि न केवल साबरमती शेड की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि भारतीय रेल की निरंतर प्रगति और यात्रियों व ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दशार्ती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीधाम-सियालदह स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम-सियालदह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तारित किया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल जिसे 08 अक्टूबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब 12 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल जिसे 11 अक्टूबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब 15 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09437 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई, 24 सितंबर, 2025

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 06 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09061/09062 बांद्रा टर्मिनस - बरौनी (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09061 बांद्रा टर्मिनस बरौनी स्पेशल को 24 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09062 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 27 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09033/09034 उधना - बरौनी (द्वि-साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09033 उधना - बरौनी स्पेशल को 25 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09034 बरौनी - उधना स्पेशल को 27 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09041/09042 उधना - बलिया (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09041 उधना-बलिया स्पेशल को 27 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09042 बलिया-उधना स्पेशल को 28 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09067/09068 उधना-जयनगर (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09067 उधना-जयनगर स्पेशल को 23 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09068 जयनगर-उधना स्पेशल को 24 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09069/09070 उधना-समस्तीपुर (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल को 23 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल को 25 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09437/09438 गांधीधाम-सियालदह (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल को 12 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल को 15 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09061, 09033, 09041, 09067, 09069 एवं 09437 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

25 सितम्बर को पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट अहमदाबाद से चलेगी

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भावनगर मंडल के पोरबंदर स्टेशन से चलने वाली ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25.09.2025 (गुरुवार) को पोरबंदर की बजाय अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन से प्रस्थान करेगी। अहमदाबाद जं. स्टेशन से प्रस्थान का समय 17.40 बजे रहेगा।

इस प्रकार यह ट्रेन पोरबंदर और अहमदाबाद के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पूर्व रेलवे क्षेत्र में कुर्मी आदिवासी आंदोलन के कारण पेयरिंग रेक 12950 सांतरागाछी-पोरबंदर कविगुरू सुपरफास्ट विलंब से संचालित हो रही है। पेयरिंग रेक की इस देरी के परिणामस्वरूप रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 25 सितम्बर को चलने वाली ट्रेन संख्या 12905 को पोरबंदर के स्थान पर अहमदाबाद से चलाया जाए।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आईसीएआर ने स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान के तहत स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां शुरू कीं 21 से 23 सितंबर तक 'स्वच्छोत्सव' मनाया

(जीएनएस)।

मौजूदा स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 2025 और वर्ष के व्यापक विषय "स्वच्छोत्सव" के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और इसके संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के नेटवर्क ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 21 से 23 सितंबर 2025 तक कई केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया।

21 सितंबर को, सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें निवारक स्वास्थ्य जांच और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव को सुगम बनाना शामिल था, जो इन महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को लेकर आईसीएआर की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

22 सितंबर को, आईसीएआर के कर्मचारियों, छात्रों और समुदाय के सदस्यों ने स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाई। इस दिन, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए "रिड्यूस, रियूज एंड रिसाईकल" के सिद्धांतों पर केंद्रित जागरूकता से संबंधित गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

यह अभियान 23 सितंबर को स्वच्छ-हरित उत्सव के साथ समाप्त हुआ, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियानों के साथ-साथ पर्यावरण-अनुकूल और शून्य-अपशिष्ट समारोहों का आयोजन किया गया। इन प्रयासों ने एक स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को दशार्या।

आईसीएआर के 113 अनुसंधान संस्थानों, 731 कृषि विज्ञान केंद्रों और देश भर के अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यान्वित इन गतिविधियों ने किसानों, छात्रों और स्थानीय समुदायों सहित हजारों हितधारकों तक पहुंच बनाई। "स्वच्छोत्सव" के तहत इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से, आईसीएआर ने न केवल स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सक्रिय भूमिका को सुदृढ़ किया, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जो ग्रामीण और शहरी भारत में दीर्घकालिक सतत विकास में योगदान देगी। ये गतिविधियां एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।

अहमदाबाद रेल मंडल में कवच प्रणाली का तेजी से विस्तार

अहमदाबाद मंडल में ट्रेन सुरक्षा के लिए 'कवच 4.0' इंस्टॉलेशन का कार्य जारी

अहमदाबाद-पालनपुर, सामाख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर कवच इंस्टॉलेशन कार्य प्रगति पर

अहमदाबाद - गेरतपुर सेक्शन पर कवच इंस्टॉलेशन पूर्ण

कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआइएल-4) के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है, लोको पायलट के ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। यह भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कम समय में भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित, परीक्षण और तैनात करना शुरू कर दिया है।

'कवच' दो स्तरों पर कार्य करता है—एक उपकरण इंजन में लगाया जाता है जिसे लोको TCAS (Train Collision Avoidance System) कहा जाता है और दूसरा स्टेशन व रेल पटरियों पर स्थापित होता है जिसे स्टेशन TCAS कहा जाता है।

अहमदाबाद मंडल में 'कवच' प्रणाली का क्रियान्वयन

भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विकसित की गई उन्नत स्वदेशी प्रणाली 'कवच' का क्रियान्वयन अहमदाबाद मंडल में भी तीव्र गति से किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. वटवा लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

वटवा लोको शेड में कुल 169 इंजनों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 23 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 146 इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए 14 प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है, जो चरणबद्ध रूप से कवच की स्थापना का कार्य कर रही है।

2. साबरमती लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

साबरमती लोको शेड में 45 हअक्र्9ल्ठउ इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है। इनमें से अब तक 7 इंजनों पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 38 इंजनों पर कार्य जारी है। इस कार्य हेतु 11 तकनीकी कर्मचारी तैनात हैं, जो कवच की सूक्ष्म स्थापना प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

3. ट्रैक सेक्शनों पर कवच इंस्टॉलेशन की स्थिति

- अहमदाबाद - पालनपुर एवं अहमदाबाद - सामाख्याली सेक्शन (कुल 402 फ्क्ट): इस रेलखंड पर कवच इंस्टॉलेशन हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। कार्य के अगले दो वर्षों में पूर्ण हो जाएगा।
- पालनपुर - सामाख्याली - गांधीधाम सेक्शन (लगभग 300 फ्क्ट): इस खंड के लिए भी निविदा जारी की जा चुकी है तथा कार्य दो वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
- अहमदाबाद - गेरतपुर सेक्शनः (13.42 ') इस सेक्शन पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है और यह खंड अब कवच से सुसज्जित हो गया है।

कवच प्रणाली में लोको पायलट को इंजन में लगे ऑपरेशन पैनल छढ-OCIP (Loco Pilot's OperÔtion-cum-Indication Panel) पर ट्रेन की जानकारी जैसे कि मालगाड़ी या सवारी गाड़ी, डिब्बों की संख्या आदि भरनी होती है। इससे कवच स्वचालित रूप से ट्रेन की लंबाई और ब्रेकिंग दूरी की गणना कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिग्नल पार कर जाने की घटनाओं SPAD (Signal Passed At Dngger), आमने-सामने या पीछे से टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकना।

भारतीय रेलवे की यह पहल न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ट्रेन संचालन को अधिक उत्तरदायी और नियंत्रित बनाती है। अहमदाबाद मंडल रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और 'कवच' प्रणाली इसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

ब्लॉक के कारण 25 सितम्बर की पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर क्षेत्र में रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाने, गोरखपुर-डोमिनगढ़ के बीच 4 किमी नई तृतीय लाइन और गोरखपुर-नखहा जंगल के बीच 5 किमी का दोहरीकरण कार्य के चलते भावनगर मंडल के पोरबंदर स्टेशन से 25 सितम्बर, 2025 (गुरूवार) को चलने वाली ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

25 सितम्बर, 2025 (गुरूवार) की ट्रेन नंबर 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी जं.-गोंडा जं.-गोरखपुर जं.-पनियहवा-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी-औंड़िहार जं.-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी।

इस मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सांगली, बापूधाम मोतिहारी और चकिया स्टेशनों पर नहीं रूकेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। उपरोक्त ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकृति दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्वीकृति दी। रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कामकाज को मान्यता देते हुए यह मंजूरी दी गई है।

प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी, लगभग 10 लाख 91 हजार अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। रेलवे के समग्र प्रदर्शन में सुधार हेतु रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी भुगतान किया जाता है।

प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपये है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी।

वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया।

जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यापक चहुंमुखी पहल

मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कुल 24,736 करोड़ रुपये की राशि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया

20,000 करोड़ रुपये के समुद्री क्षेत्र निवेश कोष के साथ समुद्री विकास निधि को मंजूरी दी गई

19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन भार तक विस्तारित करना है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इको-सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ एक मजबूत समुद्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए चहुंमुखी पहल को प्रस्तुत करता है।

इस पैकेज के तहत, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार हेतु 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन भार तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता प्रदान करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता सहित जोखिम कवरेज प्रदान करना है।

इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का विकास होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा, यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में अनुकूलन लाकर राष्ट्रीय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह भारत की भू-राजनीतिक दृढ़ता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक नौवहन एवं जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

भारत का एक लंबा और गौरवशाली समुद्री इतिहास रहा है, जिसमें सदियों पुराना व्यापार और समुद्री यात्रा इस उपमहाद्वीप को दुनिया से जोड़ती रही है। आज, समुद्री क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो देश के लगभग 95 प्रतिशत व्यापार को मात्रा के हिसाब से और 70 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से सहारा देता है। इसके मूल में जहाज निर्माण है, जिसे अक्सर "भारी इंजीनियरिंग की जननी" कहा जाता है, जो न केवल रोजगार और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वतंत्रता और व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन को भी बढ़ाता है।

कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) के सहयोग से विश्लेषणात्मक कौशल विकास पाठ्यक्रम (एएसडीसी) का आयोजन कर रहा है

(जीएनएस)।

कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी), गुरुग्राम, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान, ने आज विश्लेषणात्मक कौशल विकास पाठ्यक्रम (एएसडीसी) का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओपीसीडब्ल्यू, नीदरलैंड के सहयोग से 22 सितंबर से 03 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह की शुरूआत दीप प्रज्वलन एवं प्रशिक्षण मैनुअल के विमोचन के साथ हुई। इस सत्र में डीसीपीसी के संयुक्त सचिव (पेट्रोकेमिकल्स) श्री दीपक मिश्रा, ओपीसीडब्ल्यू के प्रतिनिधि श्री मार्टिंग ग्रांडे और आईपीएफटी के निदेशक डॉ. मोहना कृष्ण रेड्डी मुडियम के साथ-साथ कई प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

एएसडीसी कार्यक्रम 14 देशों के 16 प्रतिभागियों को एक साथ लाया है, जिनमें ओपीसीडब्ल्यू देश जैसे बुरुंडी, केन्या, युगांडा, तंजानिया, फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, जाम्बिया, लेसोथो, मोरक्को, ओमान, ब्राजील, मलावी और बारबाडोस के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं, विशेष रूप से विकासशील एवं बदलती अर्थव्यवस्थाओं से। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षमता का निर्माण करना, संस्थागत विशेषज्ञता को बढ़ावा देना एवं रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के प्रभावी कार्यान्वयन में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। एएसडीसी के व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते है, जिनमें शामिल हैं: अनुसूचित रसायनों की शब्दावली, रसायन विज्ञान, अपघटन एवं परिशोधन। उन्नत गैस क्रोमैटोग्राफी एवं मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक। नमूना तैयारी एवं व्युत्पन्नकरण विधियां। अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएं (जीएलपी) एवं ओपीसीडब्ल्यू प्रवीणता परीक्षण योजनाएं।

यह पहल न केवल सीडब्ल्यूसी से संबंधित रासायनिक विश्लेषण के लिए योग्य विशेषज्ञों के समूह को व्यापक बनाने में मदद करती है बल्कि रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों, वैश्विक मानकों के अनुपालन एवं पेशेवर समुदाय के बीच ज्ञान-साझाकरण के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व वैबिनेट मंत्री आजम खां की 23 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई तो हो गई लेकिन सवाल यह है कि 104 मुकदमों में से मात्र 12 मामलों का ही पैसला हुआ है जिनमें वे 7 में अपराध मुक्त हुए हैं जबकि 5 में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे में उनकी आजादी कितने दिनों तक रह सकेगी!

दरअसल आजम खां पर अभी भी 80 से अधिक मुकदमें उनके खिलाफ विचाराधीन हैं जिनमें 59 मजिस्ट्रेट कोर्ट, 19 सेशन कोर्ट और तीन जिला अदालतों में लंबित हैं। डूंगरपुर प्रकरण और जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी के मामले बहुत गंभीर हैं जिनमें उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा हो चुकी है। बाकी मामलों में या तो वे बरी हो गए या फिर जमानत पर हैं। आजम खां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471 और 201 जैसी गंभीर आपराधिक धाराएं लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अपने खिलाफ लगे आरोपों के खिलाफ आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुहार नहीं लगाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से लेकर सांप्रदायिक विद्वेष तक का आरोप लगाया किन्तु कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसलिए उन्हें जेल और अदालतों में ही समय बिताना पड़ रहा है। कहीं किसी एक मामले में उन्हें राहत मिल भी जाती है तो दूसरे मामले तैयार हो जाते हैं। अब भी नए मामले निकल रहे हैं जिनके लिए रामपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया है।

मतलब यह कि आजम खां खुद तो मुकदमों के जाल में फंसे हैं जबकि अखिलेश यादव उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि यदि सपा की राज्य में सरकार बनी तो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमें दर्ज हैं सारे वापस ले लिए जाएंगे।

हैरानी की बात तो यह है कि आजम खां पर सारे मामले उन्हीं दिनों के हैं जब वे मुलायम सिह एवं अखिलेश यादव के शासन काल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा गंभीर प्रवृति का नहीं है जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में रही हो। इसका मतलब है कि आजम खां ने सत्ता का दुरुपयोग अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया। इसमें उनको मुलायम और अखिलेश का भी सहयोग मिला।

बहरहाल यह तथ्य तो सार्वजनिक है कि अभी आजम खां की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए अखिलेश मुस्लिम समाज की सहानुभूति हासिल करने के उद्देश्य से भी आजम के खिलाफ मुकदमें खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह सच है कि आजम खां ने जितनी उम्मीद अखिलेश और समाजवादी पार्टी से की थी उतनी मदद न तो पार्टी से मिली और न ही यादव परिवार से। आजम खां और उनकी पत्नी तथा पुत्र सभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते किन्तु जब वे जेल गए तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य, जिला या पुलिस स्टेशन स्तर का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं समझी। यही कारण है कि आजम खां और उनका परिवार बहुत ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी और अखिलेश से नहीं करता। यही कारण है कि कुछ लाल बुझक्कड़ पत्रकार अनुमान लगा रहे हैं कि आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन यह आंकलन सही इसलिए नहीं लगता कि आजम को अपनी औकात पता है। राज्य के मुस्लिम समाज के लोगों को यदि अखिलेश और आजम खां के बीच में से एक को चुनना हो तो वे आजम को नहीं बल्कि अखिलेश को चुनेंगे। कारण है कि आजम खां ने मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है जबकि अखिलेश ने वोट के लिए मुसलमानों के हित के लिए राज्य के संसाधन का इस्तेमाल किया।

लब्बोलुआब यह है कि समाजवादी पार्टी आजम खां का नाम लेकर मुस्लिम समाज में अपनी छवि चमकाने का काम करती रहेगी किन्तु अपने

शिल्पा मलिक के नेतृत्व में बायोकैन रिसर्च ने शीर्षस्थ संस्थाओं की ओर से 50 से भी अधिक अवॉर्ड्स प्राप्त किए

उद्योग क्षेत्र में नारीशक्ति : महिला उद्यमी शिल्पा मलिक सफलतापूर्वक कर रही हैं टेक इनोवेशन आधारित स्टार्टअप

'बायोस्कैन रिसर्च' का नेतृत्व बायोस्कैन रिसर्च बनाता है ब्रेन इंजरी की तत्काल जाँच करने वाले नॉन-इन्वेसिव, पोर्टेबल ऑनसाइट डिटेक्शन टूल्स स्टार्टअप ने अब तक 70 यूनिट्स की बिक्री की है, सर्वाधिक बिक्री राज्य सरकार के प्राइमरी व कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों तथा ट्रॉमा सेंटरों में

गांधीनगर, (जीएनएस)। 24 सितंबर :समग्र गुजरात इस समय विश्व का सबसे लंबा नृत्य पर्व नवरात्रि मना रहा है। नवरात्रि का पर्व नारीशक्ति के उत्सव तथा महिलाओं की सक्षमता को उजागर करने का पर्व है। महिलाएँ आज सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं; फिर वह शिक्षा क्षेत्र हो, खेल-कूद क्षेत्र हो या उद्योग जगत। समग्र विश्व में आज जब महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और महिलाओं के नेतृत्व में सफल औद्योगिक इकाइयाँ तथा स्टार्टअप्स के अनेक उदाहरण हैं, तब गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। आज गुजरात की ऐसी ही एक महिला उद्यमी शिल्पा मलिक तथा उनके स्टार्टअप 'बायोस्कैन रिसर्च' के विषय में बात करनी है। उनके नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च आज गुजरात के एक सफल स्टार्टअप के रूप में कार्यरत है, जो जानलेवा रोगों का प्रारंभिक निदान करने वाले चिकित्सा उपकरण बनाकर अनेक लोगों का जीवन बचा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सदैव प्राथमिकता दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मोदी ने मिशन मंगलम योजना, वुमन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष महिला औद्योगिक पार्क (वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क), महिला आर्थिक विकास निगम आदि की स्थापना की। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल श्री मोदी की इन महिला केन्द्रित योजनाओं को आगे बढ़ाकर वुमन लेड डेवलपमेंट के उनके विजन को चरितार्थ कर रहे हैं।

बायोस्कैन रिसर्च बनाता है जानलेवा रोगों का प्रारंभिक निदान करने वाले चिकित्सा उपकरण

बायोस्कैन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना सितंबर-2017 में सह-संस्थापकों (को-फाउंडर्स) शिल्पा मलिक तथा अनुपम लवाणिया द्वारा अहमदाबाद में की गई थी। शिल्पा मलिक बायोस्कैन रिसर्च की को-फाउंडर तथा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। वे हार्डवेयर इनोवेशन में एक दशक का अनुभव रखने वाली एक सफल टेक्नोप्रेन्योर हैं। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैज्ञानिक के रूप में सेवा दी है तथा मिलिटरी सेंसर सिस्टम डिजाइन व मैनेजमेंट पर कार्य किया है।

शिल्पा मलिक के नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसी जानलेवा बीमारी का अनाक्रामक रूप से (नॉन-इन्वेसिवली) प्रारंभिक निदान करने के लिए चिकित्सा उपकरणों को विकसित करता है तथा उनका परीक्षण करता है और उसके बाद उनका उत्पादन करता है तथा उचित दरों पर उनकी बिक्री करता है। इस समग्र प्रक्रिया के लिए वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स तथा सॉफ्टवेयर में डीपटेक का उपयोग करते हैं। बायोस्कैन रिसर्च ने इंट्राक्रेनियल रक्तस्राव, सरल शब्दों में ब्रेन इंजरी की पहले से जाँच के लिए नॉन-इन्वेसिव, पोर्टेबल ऑनसाइड डिटेक्शन टूल्स विकसित किए हैं, जिससे समय रहते निदान कर लोगों का जीवन बचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि बायोस्कैन रिसर्च ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी (आई-क्रिएट), जो टेक इनोवेशन पर आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने वाला गुजरात सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, उससे सहायता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी)-कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (बीआईआरएसी), डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च (डीएचआर) तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से भी इस स्टार्टअप को वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 1500 रोगियों पर परीक्षण, 11 हजार से अधिक ब्रेन स्कैन

बायोस्कैन रिसर्च प्रा. लि. की जर्नी की चर्चा करते हुए उसकी को-फाउंडर शिल्पा मलिक कहती हैं, 'हमारे परिवार के सदस्य को ब्रेन इंजरी हुई थी और उसके उपचार के दौरान हमें जानने को मिला कि समस्या ब्रेन इंजरी की नहीं है, बल्कि अर्ली डिटेक्शन यानी शीघ्र निदान की है और अनेक रोगी शीघ्र निदान न हो पाने के कारण पीड़ा सहन करते हैं। हमारा बैकग्राउंड तो टेक्निकल था ही। इसलिए हमने अर्ली डिटेक्शन के लिए मेडिकल डिवाइस विकसित करने के लिए स्टार्टअप शुरू करने का निश्चय किया। हमने 4-5 वर्ष रिसर्च में लगाए और सितंबर 2017 में बायोस्कैन रिसर्च की स्थापना की।'

ब्रेन इंजरी का निदान करने वाला मेडिकल डिवाइस बनाने के बाद उसका पेटेंट फाइल करने के लिए भी उन्हें गुजरात सरकार का सहयोग मिला। उन्होंने 3 वर्ष क्लिनिकल रिसर्च के लिए लगाए। इस दौरान उन्होंने अपने बनाए डिवाइस का रोगियों पर परीक्षण किया। गुजरात में परीक्षणों के बाद समग्र भारत के विभिन्न अस्पतालों में उनके बनाए ब्रेन इंजरी के अर्ली डिटेक्शन के चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण किया गया। इनमें एनआईएमएचएएनएस-बेंगलुरू तथा एम्स-भोपास जैसे देश के अग्रणी अस्पतालों के न्यूरोसर्जन भी शामिल हुए। 2 वर्ष की क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 1500 रोगियों पर परीक्षण किया गया है और 11,000 ब्रेन स्कैन किए गए। सफल परीक्षणों के बाद उन्होंने इस डिवाइस को बिक्री के लिए लॉन्च किया।

ऑल ओवर इंडिया में लगभग 70 यूनिट्स की बिक्री, सर्वाधिक बिक्री सरकारी प्राथमिक-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

शिल्पा मलिक ने बताया कि अब तक ऑल ओवर इंडिया में वे अपने उत्पाद के लगभग 70 यूनिट्स की बिक्री कर चुके हैं। उनके द्वारा विकसित किए गए डिवाइस की परफॉर्मेंस एक्यूरेसी 95 प्रतिशत तथा सेंसेटिविटी 97 प्रतिशत है। वे कहती हैं, 'इस मेडिकल डिवाइस के लिए सरकारी विभाग से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हम सर्वाधिक डिवाइस की बिक्री भी सरकार को ही यानी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ट्रॉमा सेंटरों में करते हैं।' उनके डिवाइस की हाई एक्यूरेसी को देखते हुए डॉक्टर्स भी उन पर भरोसा जताते हैं।

बायोस्कैन रिसर्च को मिले हैं 50 से अधिक अवॉर्ड्स

शिल्पा मलिक के सफल नेतृत्व में बायोस्कैन रिसर्च को कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स/मान्यताएँ मिले हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अवॉर्ड्स निम्नानुसार हैं :

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा बेस्ट एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च अवॉर्ड (2024)
- इंडिया इजराइल इनोवेशन चैलेंज के विजेता के रूप में सम्मान
- अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई) द्वारा बेस्ट हेल्थकेयर इनोवेशन ऑफ इंडिया अवॉर्ड
- हाल ही में, जीआईटेक्स (जीटेक्स) थाईलैंड द्वारा सुपरनोवा विजेता (बेस्ट डिजी हेल्थ एंड बायोटेक इनोवेशन ऑफ इंडिया)
- यूनिट्स सीड फंड स्टारहेल्थ 2017 अंतर्गत बेस्ट हेल्थकेयर स्टार्टअप ऑफ इंडिया
- एआईसीटीई कनाडा इंडिया एक्सीलरेशन प्रोग्राम द्वारा भारत के चोटी के 10 वुमन लेड टेक स्टार्टअप्स में स्थान
- टीआईई-बीआईआरएसी डब्लूआईएनईआर द्वारा भारत के चोटी के 15 वुमन लेड बायोटेक स्टार्टअप में स्थान
- इनफोसिस स्टार्टअप-

साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन का बनाने के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर मिली मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार में 3,822.31 करोड़ रुपए की लागत से एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन का बनाने के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज बिहार में एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4-लेन का बनाने के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर है और इसमें कुल 3,822.31 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इस प्रस्तावित चार-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी पटना और बेतिया के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। इससे उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले, भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों तक जुड़ जाएंगे। यह परियोजना लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देगी, प्रमुख बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार लाएगी और कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों और सीमा पार व्यापार मार्गों से संपर्क में सुधार करके क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुगम बनाएगी।

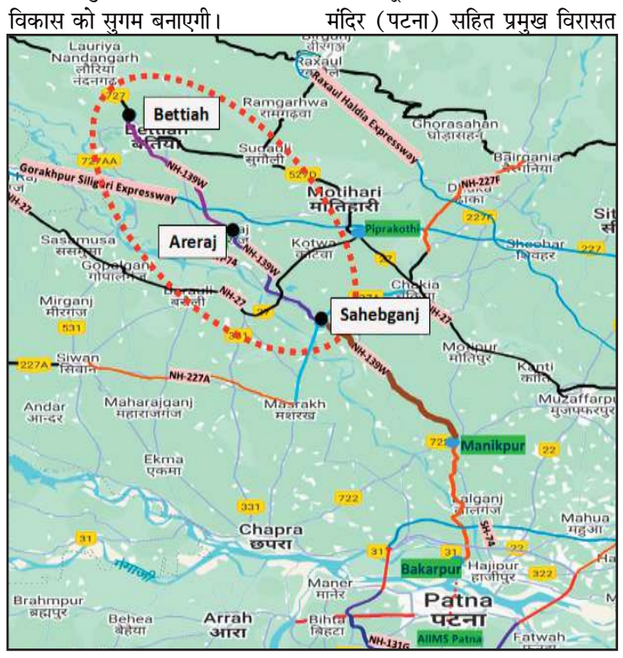

यह परियोजना सात पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, छह सामाजिक नोड्स, आठ लॉजिस्टिक नोड्स, नौ प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों को जोड़ेगी जिससे केसरिया बुद्ध स्तूप (साहेबगंज), सोमेश्वरनाथ मंदिर (अरेराज), जैन मंदिर और विश्व शांति स्तूप (वैशाली) और महावीर मंदिर (पटना) सहित प्रमुख विरासत और बौद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार होगा। इससे बिहार के बौद्ध सर्किट और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षमता को मजबूती मिलेगी।

एनएच-139डब्ल्यू की योजना वैकल्पिक मार्गों को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह एनएच-31, एनएच-722, एनएच-727, एनएच-27 और एनएच-227ए के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में काम करेगा।

यह 100 किमी/घंटा की डिजाइन गति के लिए बनाया गया है लेकिन वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा की औसत गति से चलने की क्षमता रखता है। इससे साहेबगंज और बेतिया के बीच कुल यात्रा समय, मौजूदा विकल्पों की तुलना में 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा रह जाएगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

78.94 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और इस परियोजना से अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री 25 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे

पीएमएफएमई योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण-आधारित सहायता प्रदान की जाएगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को शाम लगभग 6:15 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे।

25 से 28 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आयोजित किया जाएगा और इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व और पौष्टिक एवं जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा।

वर्ल्ड फूड इंडिया में, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,510 करोड़ रुपये से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण-आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ल्ड फूड इंडिया में सीईओ गोलमेज बैठकें, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस), बी2जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट), और जी2जी (गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट) बैठकों सहित कई व्यावसायिक बातचीत शामिल होंगी। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, इटली, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, बेल्जियम, तंजानिया, इरिट्रिया, साइप्रस, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका सहित 21 देशों के 150 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल होंगे।

वर्ल्ड फूड इंडिया में कई विषयगत सत्र भी होंगे जिनमें भारत एक वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्थायित्व और नेट जीरो, खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी, भारत का पालतू पशु आधारित खाद्य उद्योग, पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पादप-आधारित खाद्य पदार्थ, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशिष्ट खाद्य पदार्थ आदि जैसे विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें 14 मंडप होंगे, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट विषयों को समर्पित होगा। कार्यक्रम में लगभग 1,00,000 आगंतुक शामिल होंगे।

*

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता में व्यापक विस्तार को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु, केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दे दी है, ताकि 5,000 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई जा सकें। साथ ही, 1.50 करोड़ रुपये प्रति सीट लागत सीमा से सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना का विस्तार कर 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस कदम से स्नातक चिकित्सा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी; अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित होने से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी; और सरकारी संस्थानों में नए क्षेत्र में चिकित्सा विशेषज्ञता सेवा आरंभ करने में मदद मिलेगी। इससे देश में डॉक्टरों की समग्र उपलब्धता बढ़ेगी।

दोनों योजनाओं पर वर्ष 2025-26 से 2028-29 की अवधि में कुल वित्तीय परिव्यय 15,034.50 करोड़ रुपये आएगा। 15034.50 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की देनदारी 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्य की देनदारी का हिस्सा 4731.30 करोड़ रुपये होगी।

लाभ

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में मेडिकल सीट बढ़ाने की योजना से देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को खासकर वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। इससे सरकारी संस्थानों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के तहत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा का लागत-प्रभावी विस्तार भी होगा क्योंकि स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोतरी से महत्वपूर्ण चिकित्सा संवर्गों में विशेषज्ञों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इन योजनाओं का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे में लागत-प्रभावी रहते हुए स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ाना है। दीर्घावधि में, ये योजनाएं वर्तमान और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी।

रोजगार सृजन सहित प्रभावः

योजनाओं के अपेक्षित प्रमुख प्रभाव/परिणाम निम्नलिखित हैंः

भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना।

वैश्विक मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण गुणवत्ता बढ़ाना।

डॉक्टरों और विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता भारत को सस्ती दर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन भी बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सेवा पहुंच में विशेष रूप से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतर पाटा जा सकेगा।

डॉक्टरों, संकाय, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकताओं, प्रशासकों और सहायक सेवाओं से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

स्वास्थ्य प्रणाली में स्थिति अनुरूपता बढ़ेगी और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका योगदान मिलेगा।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के समान वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः

इन योजनाओं का लक्ष्य 2028-2029 तक सरकारी संस्थानों में 5000 स्नातकोत्तर सीटें और 5023 मेडिकल स्नातक सीटें बढ़ाना है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को भी मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को स्वीकृति दी, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपये है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान की, जिसकी कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना बिहार राज्य के चार जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि रहेगी।

यह रेल मार्ग राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी, जिसमें दो आकांक्षी जिलें (गया और नवादा) शामिल हैं, की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

ये मार्ग कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन साधन होने के नाते देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, साथ ही तेल आयात (5 करोड़ लीटर) को घटाएगा और सीओ2 उत्सर्जन (24 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा तथा भारतीय रेल की कार्यकुशलता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग का यह प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनाएगा और भीड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे की सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नए भारत' के विजन के अनुरूप हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनाएंगी, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने पर केन्द्रीत है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

बरेली में मिशन शक्तिः आठवीं की छात्रा सोनाक्षी बनी एक दिन की डीएसपी

(जीएनएस)।

बरेली के क्यारा ब्लॉक स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वारीनगला में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत एक अनूठी पहल की गई। विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा सोनाक्षी को एक दिन के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बनाकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना है।

डीएसपी बनी सोनाक्षी का निरीक्षण

डीएसपी की वर्दी पहनकर सोनाक्षी ने न केवल विद्यालय का

निरीक्षण किया, बल्कि सभी अध्यापकों से परिचय भी लिया। उसने प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की और अन्य छात्राओं से भी बातचीत की। सोनाक्षी ने सभी को शिक्षा का महत्व बताते हुए उच्च पदों पर पहुंचकर देश और समाज की सेवा करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान, उसने विद्यालय में बनने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को भी परखा।

विद्यालय की वार्डेन स्नेह लता शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम छात्राओं को सशक्त बनाने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी पूरन सिंह, वार्डन स्नेह लता शर्मा, और अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। यह पहल छात्राओं को यह सिखाती है कि वे भी भविष्य में बड़े पदों पर पहुंचकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा सकती हैं।

उ.प्र. के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर, 2025 को प्रारंभ हो रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो तृतीय संस्करण के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रस्तावित आगमन की पूर्व संध्या पर आज कार्यक्रम स्थल पर की गईं तैयारियों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को सफलतम बनाने की दिशा में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पैसे के विवाद में जानलेवा हमला, भतीजे ने चाचा को बेरहमी से पीटा

(जीएनएस)।

बरेलीः पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक चाचा पर उनके भतीजे और अन्य परिवार के सदस्यों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे के बंके (धारदार हथियार) से वार करके शफीक शाह नाम के व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शफीक ने अपनी जान बचाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला?

बरेली के करीमपुर चौधरी के रहने वाले शफीक शाह ने पुलिस को दिए अपने शिकायती पत्र में बताया कि करीब 5 साल पहले उन्होंने अपने भतीजे मुश्ताक शाह को गाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपये दिए थे। मुश्ताक ने इसमें से 50,000 रुपये लौटा दिए, लेकिन बाकी 1 लाख रुपये नहीं दिए।

शफीक ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मुश्ताक से पैसे वापस मांगे। इस पर मुश्ताक ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं और उसने शफीक को मोटरसाइकिल फाइनेंस पर खरीदने की सलाह दी। मुश्ताक ने यह भी वादा किया कि वह 4 महीने में 1 लाख रुपये वापस कर देगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो वह मोटरसाइकिल के फाइनेंस का ब्याज सहित 1,06,000 रुपये देगा।

इस बात पर दोनों के बीच एक रसीद भी लिखी गई थी, जिसमें मुश्ताक ने 1 अगस्त, 2025 तक 80,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उसने यह पैसा नहीं दिया।

जानलेवा हमला

बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को शफीक ने फिर से मुश्ताक से अपने पैसे मांगे। मुश्ताक ने शफीक को अपने घर बुलाया, जहां मुश्ताक, शरीफ, जसीम और अनीस पहले से मौजूद थे। जब शफीक वहां पहुंचे तो उन सबने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं।

शफीक ने जब इसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और बेरहमी से मारपीट करने लगे। इसी बीच, जसीम ने घर में रखा एक धारदार बंका निकाला और शफीक पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। बंका लगने से शफीक के सिर पर गहरी चोट आई और वे खून से लथपथ हो गए। उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं।

कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर शफीक को हमलावरों से बचाया। हमलावरों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। शफीक का कहना है कि आरोपी काफी दबंग और शातिर किस्म के लोग हैं, जिनसे उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है।

शफीक ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

बीसलपुर ब्लॉक में घटिया इंटरलॉकिंग बिछाने का आरोपः ठेकेदार रामदेव पर लगे गंभीर आरोप

पीलीभीत जिले के बीसलपुर ब्लॉक परिसर में हाल ही में बिछाई गई इंटरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार रामदेव ने सरकारी मानकों की अनदेखी करते हुए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और सरकारी धन का दुरुपयोग कर अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि यह काम अभी 6-7 महीने पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन टाइल्स धंसने लगी हैं और पूरे ब्लॉक में गड्ढों में तब्दील हो गई है।

मानकों की अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप

ब्लॉक परिसर में आने जाने वाले लोगों का कहना है कि ठेकेदार रामदेव ने इंटरलॉकिंग बिछाने में तय मानकों का पालन नहीं किया। आरोप है कि टाइल्स के नीचे रेत और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, जबकि नियमानुसार इसके लिए उपयुक्त सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठेकेदार पर सिर्फ खानापूर्ति करने का आरोप है, जिसके कारण यह काम कुछ ही महीनों में बदतर स्थिति में पहुंच गया।

अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका

इस मामले में बीडीओ और एडीओ जैसे अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि ठेकेदार ने अधिकारियों से सांठगांठ कर बिना सही जांच-पड़ताल के ही काम को पास करा लिया और सरकारी खाते से पैसा निकाल लिया। इस घटिया काम के कारण अब ब्लॉक परिसर में आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह पूरा मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। इस तरह के कामों से न सिर्फ सरकारी पैसों की बबार्दी होती है, बल्कि जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

किसान सम्मान निधि का सत्यापनः अपात्र किसानों से होगी वसूली

(जीएनएस)।

बरेली के केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फजीर्वाड़ा कर लाभ ले रहे किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसे किसानों की पहचान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिन्होंने गलत दस्तावेज जमा करके योजना का लाभ लिया है। अपात्र पाए जाने वाले किसानों से वसूली भी की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत पात्र किसानों को हर तिमाही में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। हालांकि, बरेली में 20,000 से अधिक किसानों ने गलत या अपात्र दस्तावेज दिखाकर इस योजना का लाभ लिया है। इन लोगों ने अपने दस्तावेजों में हेरफेर किया है ताकि वे योजना का फायदा उठा सकें।

केंद्र सरकार की सूची और सत्यापन का आदेश

केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों की एक सूची भेजी है, जिसके बाद कृषि विभाग को सत्यापन करने का आदेश दिया गया है। इस सत्यापन में यह पता लगाया जाएगा कि कौन से किसान वाकई इस योजना के पात्र हैं और कौन नहीं। जो किसान अपात्र पाए जाएंगे, उनके लिए मिलने वाली सम्मान निधि रोक दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें रिकवरी नोटिस जारी करके अब तक ली गई पूरी रकम वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

यह कार्रवाई उन लोगों पर शिकंजा कसेगी जो फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ताकि असली और जरूरतमंद किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंच सके।

आकांक्षी से महत्वाकांक्षी विकास खंड की ओर बढ़ता पूरेडलई ब्लॉक

(जीएनएस)।

बाराबंकी, 24 सितम्बर। जनपद बाराबंकी के अंतर्गत आने वाला पुरेडलई ब्लॉक आज आकांक्षात्मक ब्लॉकों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग द्वारा व भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित

"आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम" के अंतर्गत पुरेडलई ने जन-प्रथम शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास जैसे मानवीय सूचकांकों में शानदार प्रदर्शन किया है। विकासखंड में नीति आयोग के 40 इंडिकेटर पर सराहनीय कार्य करने के लिए जून 2025 की डेल्टा रैंकिंग में विकासखंड पूरेडलई को 500 आकांक्षी विकास खंडों में तृतीय स्थान मिला है इससे पूर्व विकासखंड को जून 2024 में अच्छे प्रदर्शन के लिऐ डेढ़ करोड़ रुपए का भी पुरस्कार दिया जा चुका है। जिससे ब्लॉक पूरेडलई उत्तर प्रदेश में सभी ब्लॉकों के लिऐ प्रेरणास्त्रोत बनाता जा रहा है।

पुरेडलई की उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षाः

टीबी उपचार में शून्य अंतराल

टीबी (तपेदिक) भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रही है। पुरेडलई ब्लॉक ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि वर्ष 2025-26 में अधिसूचित प्रत्येक टीबी रोगी का समय पर, समुचित और सफलतापूर्वक इलाज सुनिश्चित करके इसे प्रभावी ढंग से मात दी। स्वास्थ्य कार्यकताओं की सक्रियता, समयबद्ध जांच, दवा वितरण की पारदर्शी प्रणाली और रोगियों के साथ निरंतर संपर्क एवं जागरूकता कार्यक्रमों की बदौलत यह संभव हो सका।

मुख्य बिंदुः

शून्य टीबी उपचार अंतराल

100% अधिसूचित मामलों में इलाज पूर्ण

दवा वितरण की डिजिटल निगरानी व्यवस्था, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता

घर-घर जाकर संपर्क में आए संभावित रोगियों की पहचान व परीक्षण

पोषण पोटली का वितरण

100% संस्थानगत प्रसव

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र की सामाजिक प्रगति का संकेतक होता है। पुरेडलई ब्लॉक में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला का प्रसव किसी संस्थागत सुविधा में ही हो, जिससे प्रसव के दौरान किसी भी जटिलता का त्वरित समाधान हो सके। यह उपलब्धि न केवल बेहतर स्वास्थ्य ढांचे का परिणाम है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं में बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता और आशा कार्यकताओं की समर्पित भूमिका का प्रमाण है।

प्रमुख उपलब्धियाँः सभी प्रसव सरकारी अथवा पंजीकृत संस्थानों में

मातृ मृत्यु दर में शून्य की ओर प्रगति

हर गर्भवती महिला के लिए एएनसी जांच की 100% पूर्ति

नवजातों के टीकाकरण की पूर्णता दर 98%+

गुणवत्ता युक्त और समावेशी शिक्षा

शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, और पुरेडलई ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह सराहनीय है। अब सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल पुस्तकालय की स्थापना की जा चुकी है शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है। इससे सीखने की गुणवत्ता में वृद्धि, बच्चों की उपस्थिति दर में सुधार और समावेशी कक्षाओं की स्थापना हुई है।

उल्लेखनीय पहलेंः

डिजिटल लर्निंग ,(स्मार्ट क्लास) संसाधनों की उपलब्धता

बालिका शौचालय की उपलब्धता से बालिकाओं की उपस्थिति दर में 30% की वृद्धि

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए समावेशी शिक्षण उपाय

अन्य उत्कृष्ट कार्य पूरेडलई विकास खंड में।

प्रशासनिक समन्वयः खंड विकास अधिकारी, सीएचसी प्रभारी, बीईओ, सीएम फैलो, ग्राम प्रधान द्वारा ब्लॉक स्तर की सभी इकाइयों के बीच सशक्त समन्वय स्थापित किया गया।

फ्रंटलाइन कार्यबल : आशा, आंगनबाड़ी, अठट एवं शिक्षकों ने जमीनी स्तर पर नवाचारों को सफलतापूर्वक लागू किया।

सामुदायिक भागीदारी : ग्राम चौपाल, संपूर्णता अभियान, पोषण सप्ताह पोषण माह, सास बहु सम्मेलन स्वास्थ्य मेलों, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा समाज को जागरूक एवं सक्रिय बनाया गया।

डिजिटल निगरानी प्रणाली : हेल्थ व एजुकेशन डैशबोर्ड के माध्यम से सतत निगरानी और मूल्यांकन संभव हुआ।

जिला अधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा,

ह्लपूरेडलई ब्लॉक की यह ऐतिहासिक सफलता जिला और ब्लॉक प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सभी ने शासन की नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में काम किया है, और यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रही।'

मुख्य विकास अधिकारी श्री अ. सुदन ने कहा कि

ह्लस्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मानकों पर केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से पूरेडलई ब्लॉक ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। टीम भावना, सतत निगरानी और नवाचारपूर्ण पहलों के कारण यह संभव हो पाया है।'

खंड विकास अधिकारी श्री शिवजीत ने कहा कि पूरेडलई ब्लॉक ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विद्यालयों में नामांकन व उपस्थिति बढ़ाने, पोषण स्तर को बेहतर करने, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है जिससे यह रैंक हासिल हुई है।

भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा पुरेडलई की इस प्रगति की सराहना करते हुए इसे "स्थानीय नेतृत्व और नवाचार आधारित विकास का मॉडल" घोषित किया गया है। आयोग ने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी यदि नेतृत्व स्पष्ट हो, और समुदाय जागरूक हो, तो असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

लीलौर झील में हादसाः नौका विहार के दौरान किशोर की डूबकर मौत, सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

(जीएनएस)।

बरेली के आंवला स्थित लीलौर झील में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नौका विहार के दौरान 16 वर्षीय किशोर जितेंद्र उर्फ भोला की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को हुई, और लगभग 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। यह हादसा झील में सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

उद्घाटन के बाद भी सुरक्षा की अनदेखी

यह घटना इस बात को दशार्ती है कि लीलौर झील का उद्घाटन 15 अगस्त, 2025 को एक कैबिनेट मंत्री और बरेली के जिलाधिकारी की मौजूदगी में धूमधाम से हुआ था,

लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बोटिंग के लिए लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार, लाइफ जैकेट सिर्फ उद्घाटन के समय नेताओं और अधिकारियों के लिए ही इस्तेमाल की गई थीं।

लापरवाही और जवाबदेही की कमी

हादसे के बाद भी, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी 15 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में इस अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

सुरक्षा को लेकर सरकारी परियोजनाओं में कितनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। एक मासूम की जान जाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुली है। अब देखना यह है कि क्या इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी।

बरेली में अवैध मेडिकल स्टोरों का जालः एक लाइसेंस पर चल रही हैं कई दुकानें

(जीएनएस)।

बरेली में औषधि विभाग की कथित मिलीभगत से अवैध मेडिकल स्टोरों का बड़ा कारोबार फल-फूल रहा है। आरोप है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर कई-कई मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लाइसेंस और दुकानों की संख्या में बड़ा अंतर

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगभग 6100 मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, लेकिन औषधि विभाग के पास केवल 3000 ही पंजीकृत हैं। यह बड़ा अंतर इस बात की ओर इशारा करता है कि

या तो 3100 दुकानें बिना किसी पंजीकरण के चल रही हैं, या फिर एक ही लाइसेंस पर कई दुकानों का संचालन हो रहा है।

शहर के मुख्य थोक दवा बाजार शास्त्री मार्केट और गली नवाबान से करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। बताया जा रहा है कि यहां कई थोक विक्रेता एक ही लाइसेंस पर चार से पांच दुकानें चला रहे हैं।

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

यह चौंकाने वाला सच विभागीय अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों का इन अवैध कारोबारियों से अपना हित जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वे जांच और कार्रवाई से कतराते हैं। हालांकि, औषधि विभाग के अधिकारी समय-समय पर जांच का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस अवैध कारोबार से न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि मरीजों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है।